(iv) CONSTRUCTION OF TALCHAR-SAMBALPUR RAILWAY LINE IN ORISSA

SHRI K. P. SINGH DEO (Dhenkaual) : The emotional integration of Orissa and the economic development of the State suffered greatly due to lack of direct link between the coastal and the western regions of the State. The western districts of Sambalpur, Bolangir, Kalahandi and Sundargarh possess large mineral bearing areas with huge reserves of coal, lime stone, bauxite, china clay, rich forest areas and an agricultural belt but due to want of direct communication, these resources are not being exploited economically and fully. In view of the above, the State Government have been urging the Railway Ministry to construct the 160 KM strip linking Talcher and Sambalpur, which would open the very rich hinterland for the Paradeep Port as it will reduce the distance between Sambalpur and Bhubaneshwar by about 470 KM, will bring Rourkela, Bhilai and the Raipur industrial belt nearer to the port of Paradeep and will offer direct and most economical route between the Alumina complex at Koraput, the Aluminium Smelter at Angul and the Talcher coal-field.

A survey was conducted by the S. E. Railway, but the survey suffered from the basic defect that it had not taken into consideration the very significant developments, namely, the setting up of the steel plant, oil terminal and a fertiliser plant at Paradeep and the Alumina complex near Koraput, Aluminium Smelter at Angul and the resultant increase in traffic movement that will arise from them. A second survey was, therefore, ordered and the report is now available. The latest report shows that the earning from this line would be 5.10 per cent as against 4.23 per cent as in the first report and including the cost of land to be given free it will be 6.62 per cent and eventually it will cross the 12 per cent mark when ancillary units come up.

The Railway Administration pays dividend to the General Revenue at the rate of 6 per cent and if we add concessions which the Railway give for constructing railway lines in hilly and difficult areas for computing traffic growth, the financial return would come to 10 per cent and would make the line wholly viable.

It may be mentioned that the creation of this link has also been specifically recommended by the National Transport Policy Committee in para 9.3.3. Recent developments have further brightened the prospects of increased traffic on this line. According to present indications Talcher mines will be required to supply five million tonnes of coal to Vizag Steel Plant and this will greatly augment the traffic on this line.

Now that the Railway survey has found the project to be viable, the National Transport Policy Committee has recommended it and it has immense potential for traffic growth, I request the Railway Minister to include it in the Sixth Plan without any further delay.

(v) CRISIS IN HANDLOOM INDUSTRY DUE TO INCREASE IN PRICE OF COTTON/SILK YARN.

श्री अशफाक हुसेन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हैंडलूम में इस्तेमाल होने वाले सूत और रेशमी धागे के दाम में पिछले तीन महीनों में लगातार इजाफे ने इस सब से बड़ी घरेलू सनअत को बुहरान में मुबतिला कर दिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दूसरे हैंडलूम मरकजों हर जहां 20 और उससे नीचे के नम्बरों का सूत इस्तेमाल होता है उस की हालत खसूसी तौर पर बदतर हो गई है। बीस और उससे नीचे के नम्बर का जो सूत अभी दोमह किब्ल नब्बे और बानवे में फरोख्त होता

[श्री अशफाक हुसेन]

था वह आजकल 120 और 122 रुपये में दस्तयाब है। परेशानी तो इस बात की है कि सरकारी या कोआपरेटिव इदारे जो बुनकरों की जरूरत का बीस से पच्चीस फीसदी सूत ही फराहम करते हैं वह भी अपने डिपो के सूत की कीमत बजार निरख पर बढ़ाते जाते हैं। मरकज का कौमी हैंडलूम गवर्नमेंट कारपोरेशन दो साल बाद भी अभी वजूद में नहीं आ सका है। हैंडलूम सनअत को अच्छा और सस्ता सूत साल भर के लिए एक दाम पर उस वक्त तक पाबन्दी से नहीं मिल सकता जब तक मरकजी हकूमत सूत तैयार करने वाली सभी कोआपरेटिव और प्राइवेट कताई मिलों पर चीनी की तरह की लेवी लगा कर हैंडलूम की जरूरत का सारा सूत मुनासिब दाम पर लेकर अपने इदारों से बुनकरों तक न पहुँचायें।

इस काम में मुजब्बज कौमी हैंडलूम गवर्नमेंट कारपोरेशन, रियासती कारपोरेशन और रियासतों के को-आपरेटिव इदारे उसी वक्त अपना रोल अदा कर सकते हैं जब उनको कताई और कम्पोजिट मिलों से साल भर तक एक ही दाम पर हैंडलूम की जरूरत का सारा सूत चीनी की लेवी के तरीके पर सरकार फराहम करने की जिम्मेदारी ले। मरकजी हकूमत के इस सिलसिले में फौरी और बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है और मरकजी वजीरे तिजारत को इस सिलसिले में बयान देना चाहिए।

[شری اشفاق حسین (مہاراج گنج):

ہینڈ لوم میں استعمال ہونے والے سوت اور ریشمی دھاگے کے دام میں پچھلے تین مہینوں میں لگاتار اضافے

اس سب سے بڑی گھریلو صنعت کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے - اُترپردیش ہریانہ پنجاب اور دوسرے ہینڈ لوم مرکزوں پر جہاں بیس اور اس سے نیچے کے نمبروں کا سوت استعمال ہوتا ہے کی حالت خصوصی طور پر بد تر ہوگئی ہے - بیس اور اس سے نیچے کے نمبر کا جو سوت ابھی دو سال قبل نوے اور بانوے روپئے میں فروخت ہوتا تھا وہ آج کل ایک سو بیس اور ایک سو بائیس روپئے میں دستیاب ہے - پریشانی تو اس بات کی ہے کہ سرکاری یا کوآپریٹو ادارے جو بنکروں کی ضرورت کا بیس سے پچیس فیصد سوت ہی فراہم کرتے ہیں وہ بھی اپنے ڈپو سے سوت کی قیمت بازار نرخ پر بڑھاتے جاتے ہیں - مرکز کا قومی ہینڈ لوم ڈیولپمینٹ کارپوریشن دو سال بعد بھی ابھی وجود میں نہیں آسکا ہے -

ہینڈ لوم صنعت کو اچھا اور سستا سوت سال بھر کے لئے ایک دام پر اس وقت تک پابندی سے نہیں مل سکتا جب تک کہ مرکزی حکومت سوت تیار کرنے والی سبھی سرکاری کوآپریٹو اور پرائیویٹ کتائی ملوں پر چینی کی طرح کی لیوی لگا کر ہینڈ لوم کی ضرورت کا سارا سوت مناسب دام پر لے کر اپنے اداروں سے بنکروں تک نہ پہنچائے - اس کام

میں مجوزہ قومی ہینڈ لوم ڈیولپمینٹ کارپوریشن ریاستی کارپوریشن اور ریاستوں کے کوآپریٹو ادارے اسی وقت اپنا رول ادا کر سکتے ہیں جب ان کو کتائی اور کمپوزٹ وارن سے سال بھر تک ایک ہی دام پر ہینڈ لوم کی ضرورت کا سارا سوت چینی کی لدوم کے طریقے پر سرکار فراہم کرنے کی ذمہ داری لے مرکزی حکومت کے اس سلسلے میں فوری اور بنیادی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور مرکزی وزیر تجارت کو اس سلسلے میں بیان دینا چاہئے -]

(vi) DEMOLITION OF STAFF QUARTERS IN THE GOLE MARKET AREA OF NEW DELHI.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आज जब दिल्ली में बड़े पैमाने पर अनधिकृत बस्तियों का निर्माण हो रहा है और ऐसे निर्माण को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, यह बड़े दुख और रोष की बात है कि 25 वर्षों से सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले घरेलू कर्मचारियों को उनके बने बनाए घरों से उजाड़ा जा रहा है। दिनांक 5 दिसम्बर 1981 को जब गोल मार्केट के निकट बने हुए घरेलू कर्मचारी क्वार्टरों में रहने वाले लोग रोटी और रोजी कमाने अपने काम पर गये हुए थे केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों ने पुलिस की सहायता से उन घरों पर धावा बोल दिया, जीने तोड़ दिये, किवाड़ उखाड़ दिये और गरीबों का सामान—उन का सामान होता ही कितना है—बाहर सड़क पर फेंक दिया। मैं उसी रात को लगभग 12 बजे के करीब इन दुखी व्यक्तियों की चीख-पुकार सुन कर घटना स्थल पर गया था। कड़कड़ाती सर्दी, वर्षा, खुले आसमान के नीचे, इन निरीह तथा निर्दोष व्यक्तियों का कुनबा इधर उधर बिखरे हुए सामान के बीच और पुलिस की घेराबन्दी के मध्य आग ताप कर घड़ियां बिता रहा था।

इन अभागे गरीबों ने मुझे जो कुछ बताया उसके अनुसार ये लोग वर्षों से इन सर्वेंट क्वार्टरों में रहते हैं और पानी आदि का खर्चा भी देते हैं। जब केन्द्रीय कर्मचारियों के ये क्वार्टर तोड़े गये और नये क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ हुआ, तो ये लोग बेघरबार हो कर कहां जाएंगे, इसका विचार नहीं किया गया और न कोई समुचित व्यवस्था ही की गई। कर्मचारियों के अनुसार ये अपना मामला अदालत में भी ले गये हैं और अदालत का फैसला 11 दिसम्बर को होना है। किन्तु अदालत के फैसले की प्रतीक्षा किये बिना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुलिस की सहायता से इन्हें उजाड़ दिया। यह घटना संसन भवन से थोड़ी ही दूर पर हुई है। कहा जाता है कि यहां बगीचा लगाने के लिए इन मकानों को गिराना जरूरी है। बसे बसाये लोगों को उजाड़ कर जो बाग लगाना चाहते हैं उनके हृदय में कितनी मानवीय संवेदना है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि इन क्वार्टरों को गिराने और लोगों को बेघर बनाने का कार्य क्या तब तक नहीं रोका जा सकता था जब तक सर्दी कुछ कम नहीं हो जाती और बच्चों की पढ़ाई का साल भी पूरा नहीं हो जाता।

मेरी मांग है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री इस सम्बन्ध में सारी स्थिति को स्पष्ट करें। सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम निर्माण होना चाहिए, ध्वंस नहीं।